भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका

नरेन्द्र कुमार ढाका
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय महाविद्यालय
इटावा, कोटा
ईमेलः narendrajumardaka@fmail.com

सारांश *जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक और राजनीतिक संरचना का एक प्रमुख पहलू है। जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे प्राचीन विशेषता है और यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और कार्यों में एक प्रमुख कारक है। जाति शब्द स्पेनिश शब्द कास्ट से लिया गया है जिसका अर्थ है नस्ल। किसी विशेष नस्ल में पैदा हुए लोगों की अपनी अलग जाति होती है। यह व्यक्ति के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को परिभाषित करती है। जाति भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक उल्लेखनीय आधार है।*

भारतीय राजनीति जाति से ग्रस्त राजनीति है। जाति राजनीतिक दलों, हित समूहों और सभी राजनीतिक संरचनाओं और उनके कार्यों की प्रकृति, संगठन और कार्यप्रणाली को निर्धारित करती है। भारतीय समाज जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर अत्यधिक विभाजित हो गया है, जो अंततः संसदीय लोकतंत्र के सही कामकाज को रोकता है। इस पेपर का मूल उद्देश्य भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण करना है और यह कैसे गंभीर चिंता का एक प्रमुख कारण बन जाता है और राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा बन जाता है।

मुख्य बिन्दु

जाति, वर्ग, राजनीति, पार्टी, समाज।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 10.08.2024
Approved: 27.09.2024

नरेन्द्र कुमार ढाका

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका
RJPP April 24-Sept.24, Vol. XXII, No. II,

PP. 148-152
Article No. 18

Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2024-vol-xxii-no2

परिचय

समकालीन भारतीय परिदृश्य में, जाति लामबंदी भारतीय राजनीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। रिसले के अनुसार जाति, एक सामान्य नाम रखने वाले परिवारों का एक समूह है, जो एक पौराणिक पूर्वज, दैवीय या मानव से एक सामान्य वंश का दावा करते हैं और एक ही वंशानुगत व्यवसाय का पालन करने का दावा करते हैं और जो लोग एक राय देने में सक्षम हैं, वे इसे एक एकल समरूप समुदाय के रूप में मानते हैं। जाति को स्थानीयकृत समूह के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका जाति में जन्म के आधार पर पारंपरिक जुड़ाव होता है, हालांकि कभी–कभी यह विशेष व्यवसाय से जुड़ा होता है (एन.डी. अरोड़ा, 2010)।

जाति, अपने सदस्यों के संयुक्त प्रयास से, वर्तमान में राजनीति और प्रशासन दोनों में मुख्य रूप से मताधिकार और पंचायती राज जैसी संस्थाओं के माध्यम से हस्तक्षेप कर रही है। चाहे वह भारतीय राजनीतिक दलों की गुटबाजी हो या उम्मीदवारों का नामांकन और चुनाव प्रचार का तरीका, अधिकांश चीजों को जातिगत हितों और जातिगत संतुलन के माध्यम से समझाया जा सकता है। जाति व्यवस्था, जो शुद्धता और प्रदूषण, पदानुक्रम और अंतर के दर्शन पर आधारित है, सामाजिक गतिशीलता के बावजूद शूद्रों और बहिष्कृत लोगों के प्रति अत्याचारी रही है, जिन्होंने अनुष्ठानिक अशुद्धता के अपमान को झेला और घोर गरीबी, अशिक्षा और राजनीतिक सत्ता से वंचित रहे। जाति पर आधारित टकरावपूर्ण पहचान की राजनीति का आधार यह कहा जा सकता है कि यह उत्पीड़ित जाति समूहों को सुरक्षात्मक भेदभाव के रूप में राज्य का समर्थन प्रदान करने के मुद्दे पर आधारित है। जाति पर आधारित यह समूह पहचान, जो जातिगत पहचानों के इर्द–गिर्द राजनीतिक चेतना के आगमन से मजबूत हुई है, जाति–आधारित राजनीतिक दलों द्वारा संस्थागत रूप ले ली गई है, जो जातियों सहित विशिष्ट पहचानों के हितों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने को स्वीकार करते हैं। इसके बाद, राजनीतिक दलों में उच्च जाति का वर्चस्व भाजपा, निचली जाति का वर्चस्व बसपा (भोज समाज पार्टी) या सपा (समाजवादी पार्टी) है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि वामपंथी दलों ने चुनावी राजनीति में दूरी बनाने के लिए जाति के पैटर्न का स्पष्ट रूप से पालन किया है।

राजनीतिकरण के समग्र परिणाम को इस तर्क से स्पष्ट किया जा सकता है कि जाति–आधारित पहचान की राजनीति ने भारतीय समाज और राजनीति में दोहरी भूमिका निभाई है। इसने तुलनात्मक रूप से जाति–आधारित भारतीय समाज को लोकतांत्रिक बनाया लेकिन साथ ही वर्ग–आधारित संगठनों के विकास को अस्थिर किया। ऐतिहासिक तथ्यों ने संकेत दिया कि जाति–आधारित भेदभाव और वर्चस्व भारतीय समाज का एक दुर्भावनापूर्ण पहलू रहा है और स्वतंत्रता के बाद, राजनीति के साथ इसके निहितार्थों ने न केवल पहले से उत्पीड़ित जाति–समूहों को राजनीतिक स्वतंत्रता और मान्यता प्रदान करना संभव बनाया है, बल्कि राजनीतिक पूंजी के रूप में इसकी क्षमता के बारे में चेतना भी जगाई है। वास्तव में, दीपांकर गुप्ता ने भावनात्मक रूप से इस अस्पष्टता को उजागर किया है जब वह जाति के बारे में अंबेडकर और मंडल आयोग के दृष्टिकोण के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। जबकि पूर्व ने भारतीय सामाजिक जीवन और राजनीति से अस्पृष्यता को एक संस्था के रूप में हटाने के लिए आरक्षण या सुरक्षात्मक भेदभाव की नीति तैयार की, बाद वाले ने जाति को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संसाधन माना।

वास्तव में, मंडल आयोग को जाति आधारित पहचान को एक ऐसी संपत्ति में बदलने में बौद्धिक प्रेरणा के रूप में माना जा सकता है जिसका उपयोग राजनीतिक और आर्थिक लाभों की सुरक्षा के लिए आधाार के रूप में किया जा सकता है। यद्यपि यह भी कहा जा सकता है कि उच्च जातियां अपनी प्रमुख स्थिति के कारण पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में ताकतवर पदों पर आसीन थीं, और जब मंडल ने जाति–पहचान के उनके नुकसान को एक लाभ के रूप में पहचान कर दलितों की चेतना को तीव्र किया तो टकराव शुरू हो गया।

उद्देश्य

- जाति किस हद तक और किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है
- जाति और राजनीति के बीच अंतर्संबंध, और
- राजनीति जाति को कैसे प्रभावित करती है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जाति की भूमिका पर विशेष रूप से इस प्रकार चर्चा की जा सकती है

(1) राजनीतिक समाजीकरण और नेतृत्व भर्ती में जाति कारक– विभिन्न जाति समूहों की अलग–अलग राजनीतिक पार्टियों और उनकी विचारधाराओं के प्रति अपनी निष्ठा होती है। अपने जन्म से ही, एक भारतीय नागरिक को एक जाति विरासत में मिलती है और वह एक विशेष जाति समूह के सदस्य के रूप में बड़ा होता है। वह या तो उच्च जातियों में से एक या अनुसूचित जातियों में से एक होता है। अपने राजनीतिक झुकाव, दृष्टिकोण और विश्वासों को अपनाने की प्रक्रिया में, वह स्वाभाविक रूप से जाति समूहों और जातिवाद के प्रभाव में आ जाता है। 'जाति मूल्य' और जाति हित उसके समाजीकरण और परिणामस्वरूप उसकी राजनीतिक सोच, जागरूकता और भागीदारी को प्रभावित करते हैं। वह नेतृत्व की भूमिका निभाने और उसे निभाने के लिए जाति की एकजुटता पर निर्भर करता है। जाति नेतृत्व भर्ती की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यह हरियाणा, बिहार, यूपी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के अत्यधिक 'जाति जागरूक' लोगों के लिए विशेष रूप से सच है। हरियाणा में नेतृत्व या तो जाटों से आता है या बिश्नोई या ब्राह्मणों से। आंध्र प्रदेश में रेड्डी, कम्मा और वलामा राज्य के नेता प्रदान करते हैं।

(2) जाति और पार्टी की राजनीति– जाति कारक भारतीय पार्टी प्रणाली का एक घटक है। कुछ राजनीतिक दलों का सीधा जाति आधार होता है जबकि अन्य अप्रत्यक्ष रूप से विशेष जाति समूहों पर निर्भर होते हैं। विशेष रूप से, क्षेत्रीय राजनीतिक दल मुख्य रूप से जाति कारक से प्रभावित होते हैं। DMK vs AIADMK तमिलनाडु के गैर–ब्राह्मण बल्कि ब्राह्मण विरोधी राजनीतिक दल हैं। पंजाब में, अकाली दल की एक सामुदायिक पंथिक पहचान है, लेकिन जाट बनाम गैर–जाट के मुद्दे से प्रभावित है। भारत में सभी राजनीतिक दल चुनावों में वोट हासिल करने के लिए जाति का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ बीएसपी अनुसूचित जातियों के समर्थन पर निर्भर करती है, वहीं भाजपा मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदुओं और व्यापारिक समुदाय के बीच अपनी लोकप्रियता पर निर्भर करती है। वास्तव में, भारत में भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी नीतियों और निर्णयों को तैयार करते समय लगभग हमेशा जाति कोण को ध्यान में रखता है।

(3) जाति और चुनाव– भारत में चुनावी राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चयन, उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र आवंटित करने और चुनाव में अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने में जाति के कारक को बहुत महत्व देते हैं। मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रां में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाते हैं और जाट बहुल क्षेत्रों में जाट उम्मीदवार उतारे जाते हैं। कांग्रेस, जनता दल, सीपीआई और सीपीएम जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों के चयन में जाति के कारक को ध्यान में रखती हैं। चुनाव प्रचार में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। प्रतिबद्ध समर्थन के लिए जाति समूहों का सहारा लिया जाता है। एन.डी. पामर की इस बात से कोई असहमत नहीं हो सकता कि उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से अपील करने में जाति के विचारों को बहुत महत्व दिया जाता है। चुनावों में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के रूप में कार्य करती है।

(4) भारतीय राजनीति में जाति एक विभाजनकारी और एकजुट करने वाली ताकत के रूप में– भारतीय राजनीति में जाति एक विभाजनकारी और एकजुट करने वाली ताकत के रूप में कार्य करती है। यह भारतीय व्यवस्था में कई हित समूहों के उद्भव के लिए एक आधार प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक सत्ता के संघर्ष में हर दूसरे समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। कई बार यह सत्ता के लिए अस्वस्थ संघर्ष की ओर ले जाता है और एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, यह विभिन्न समूहों के सदस्यों के बीच एकता का स्रोत है और एक सामंजस्यपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करता है।

ग्रामीण भारत में, जहाँ ग्रामीण सत्ता का सामाजिक ब्रह्मांड 15 से 20 किमी के क्षेत्र तक सीमित है, जाति एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है। यह एकमात्र सामाजिक समूह है जिसे वे समझते हैं। हालाँकि, दो या तीन बड़े जाति समूहों का अस्तित्व भी गुटबाजी की ओर ले जाता है। जाति भारतीय राजनीति में एक मजबूत कारक है और यह एक सामंजस्यपूर्ण और साथ ही एक विभाजनकारी कारक के रूप में कार्य करती है।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र के अंत में हम कह सकते हैं कि जाति भारतीय सामाजिक संरचना में बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है और राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। पार्टी गठन से लेकर निर्णय लेने तक, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

वयस्क मताधिकार की शुरुआत के बाद, हर वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गया और प्रत्येक पार्टी ने अधिक से अधिक मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। आजकल राजनीति के लिए जाति और राजनीति के लिए जाति का महत्व बढ़ गया है। कभी–कभी राजनीतिक दल जाति आधारित नारे और अन्य चीजों का उपयोग करके इस जाति व्यवस्था को बढ़ाते हैं। इसने सामाजिक सद्भाव को नष्ट कर दिया और समाज में हिंसा को जन्म दिया। समाज के विकास के लिए जातिवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है। सरकार को इस बुराई को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को भी सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विकास के लिए यह बहुत जरूरी है।

संदर्भ

1. सुश्री दीपिका गहतराज, मॉड्यूलरू टप, क्षेत्रवादः जाति और भाषाई राजनीति विशयः राजनीति विज्ञान पंचम्।
2. प्रो. यमुना ए कोनेसर, "भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और जातीयता'' 2018 प्श्रब्ज्ए खंड 6, अंक 2 मई 2018, प्ैछरू 2320–288।
3. हरदीप कौर, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका प्ैछ (प्रिंट) 2393–8374, (ऑनलाइन): 2394–0697, खंड–5, अंक–1, 2018।
4. भारत में जाति, वर्ग और राजनीति सामग्री को ई–ज्ञानकोष, इग्नू
5. नीलम देवी, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जर्नल ऑफ एडवांस एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेषन, मल्टीडिसिप्लिनरी एकेडमिक रिसर्च
6. श्रीनिवास, एम.एन. (1962), आधुनिक भारत में जातिरू और अन्य निबंध, एषिया पब्लिषिंग हाउस, बॉम्बे
7. कोठारी, रजनी (1970). भारत में राजनीति, बोस्टन, लिटिल ब्राउन.
8. येल जर्नल ऑफ इंटरनेषनल लॉ, खंड 35